

पुपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▶ Issue : 22 ▶ Mumbai ▶ Friday, 3 July to 9 July 2026 ▶ Weekly ▶ Pages : 8 ▶ Price : 3 Rs.

जनजातीय
युवाओं को
बदलाव
के लिए

मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू



विशाखापत्तनम: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को जनजातीय समाज के आत्मविश्वास, नेतृत्व

और नीति निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने वाला प्रमुख केंद्र बनना चाहिए तथा शिक्षा के माध्यम से जनजातीय समुदायों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय पर अनेक विशेष

जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य से स्थापित ऐसे संस्थानों का दायित्व केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका और वनाधिकारों के क्षेत्र में भी जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में जनजातीय युवाओं के सर्वांगीण विकास और क्षेत्र के समग्र उत्थान के लिए सार्थक प्रयास करेगा। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय, विशेषकर जनजातीय विश्वविद्यालयों में, ऐसी नवाचारी व्यवस्थाएं विकसित की जानी चाहिए, जिनसे वन उपज, हस्तशिल्प, मिलेट, औषधीय पौधों, इको-टूरिज्म और स्थानीय उद्यमिता जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सके। (शेष पेज 3 पर)

भारत-जापान के बीच रक्षा क्षेत्र की पहली सह-विकास परियोजना पर हुआ समझौता एआई और सेमीकंडक्टर सहयोग को भी मिलेगी नई रफ्तार : प्रधानमंत्री मोदी



नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष साने ताकाची ने गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की, क्योंकि भारत और जापान ने अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और गहरा करने की मांग की। राष्ट्रपति

भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री ताकाची का औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद यह बैठक हुई, जहां पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलवाया। (शेष पेज 5 पर)

संक्षिप्त खबरें

लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन बने भारतीय सेना के नए उप प्रमुख

नई दिल्ली: भारतीय सेना में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, सेना के उप प्रमुख (वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने 1 जुलाई को नई दिल्ली में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि लगभग चार दशक लंबे सैन्य करियर में लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने विभिन्न चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कमान संभालते हुए नेतृत्व, संचालन और रणनीतिक योजना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव अर्जित किया है। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को जून 1988 में महार रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त हुआ था।



केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का बढ़ाया कार्यकाल

नई दिल्ली: विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल तय समय से एक साल आगे बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी बुधवार को दी गई। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी विक्रम मिस्त्री के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उनका मौजूदा कार्यकाल 14 जुलाई 2026 को खत्म होना था, लेकिन अब वह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) की ओर से जारी यह ऑर्डर फंडामेंटल रूल 56(डी) के प्रोविजन्स को लागू करता है।

संसद का मानसून सत्र 20 से शुरू होने की संभावना

► कई अहम विधेयक पेश करेगी सरकार

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है और इसके तीन सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हालांकि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति को अभी इस पर अंतिम निर्णय लेना है। आमतौर पर मानसून और शीतकालीन सत्रों में 20 बैठकें होती हैं और ये चार सप्ताह तक चलते हैं। लेकिन कम अवधि वाले सत्रों के उदाहरण भी रहे हैं। इस मानसून सत्र की शुरुआत बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत के बाद हो रही है। इस सत्र में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में हुई बगावत का असर भी देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों की अलग समूह के तौर पर मान्यता की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले का इंतजार है।



वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में राजनाथ सिंह बोले

विकसित भारत की यात्रा में क्षेत्रीय उद्योगों की अहम भूमिका

बडोदरा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में क्षेत्रीय उद्योगों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ह्यविकसित भारत केवल आर्थिक प्रगति का लक्ष्य नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से सशक्त राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। इसके लिए जरूरी है कि क्षेत्रीय क्षमताओं को राष्ट्रीय ताकत में बदला जाए और स्थानीय नवाचारों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक पहुंचाया जाए। रक्षा मंत्री



मंगलवार को बडोदरा में आयोजित ह्यावाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में उद्योगपतियों, उद्यमियों, युवा इनोवेटर्स और शिक्षाविदों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मन्त्र पालन,

पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. मनीषा भी मौजूद रहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में भारत की भूमिका उसकी आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और सामूहिक संकल्प से तय होगी। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्र तीन प्रमुख स्तंभों, आर्थिक मजबूती, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा, पर खड़े होते हैं। (शेष पेज 5 पर)

NEET और JEE एंट्रेंस एग्जाम में 12वीं बोर्ड का मिल सकता है 50% वेटेज



नई दिल्ली: NEET और JEE एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर में बोर्ड एग्जाम में मिले नंबरों को 50% वेटेज दिया जा सकता है। अभी इस फैसले पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस संभावना पर इसलिए विचार किया जा रहा है ताकि किसी भी एग्जाम का बहुत ज्यादा दबाव कम किया जा सके, चाहे वह मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशन के

बदल सकता है NEET-JEE का एग्जाम पैटर्न

■ NEET-JEE के एग्जाम पैटर्न में जिन बदलावों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एडमिशन/मेरिट में बोर्ड के मार्क्स को 50% वेटेज देना, कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता कम करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट को स्कूल के सिलेबस से बेहतर ढंग से जोड़ना शामिल है। इसके साथ ही कई बार एग्जाम देने का मौका देना और धीरे-धीरे अडेप्टिव ऑन-डिमांड कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट की ओर बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।

लिए एंट्रेंस टेस्ट हों या बोर्ड एग्जाम। यह कदम एग्जाम सिस्टम में कई गड़बड़ियों जैसे मूल्यांकन में गलतियां और पेपर लीक होने के बाद उठाया जा रहा है, जिससे प्रवेश परीक्षा के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए थे। (शेष पेज 3 पर)

देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव

ईएसआइसी को मिली नए अस्पतालों की जिम्मेदारी

नई दिल्ली: देशभर में हाल ही में शुरू किए गए और भविष्य में बनने वाले सभी नए अस्पतालों का संचालन अब राज्य सरकारों के बजाय सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) द्वारा ही किया जाएगा। श्रम एवं रोजगार और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईएसआइसी की 198वीं बैठक में यह फैसला किया गया। वर्तमान में राज्य सरकारों के अधीन और पुनर्निर्माण या उन्नयन के दौर से गुजर रहे अस्पतालों का प्रबंधन राज्य सरकारें तब तक करती रहेंगी जब तक कि वह ईएसआइसी को सौंपने का विकल्प नहीं चुनती। निगम ने ईएसआइसी की आयुष सेवाओं के एकीकरण, सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के लिए एक संयुक्त ढांचा बनाने और जीवन शैली से संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और ईएसआइसी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।



संपादकीय

शिक्षा बने जीवन दृष्टि का आधार

लम्बे समय से भारत में शिक्षा व्यवस्था असमानता और व्यावसायिकता की शिकार बनती दिख रही है। इस माहौल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल में कोचिंग पर छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए कमेटी का गठन सराहनीय कदम ही कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि कमेटी का गठन महज औपचारिकता बनकर ही रह जाएगा या फिर कोई ठोस सुझावों के साथ बदलाव के सुझाव सामने आएंगे। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि हमारे देश में कोचिंग का कारोबार लगातार फल-फूल रहा है। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में संध लगाते हुए कई कोचिंग संस्थान तो सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा तक को प्रभावित करने लगे हैं। कोचिंग संस्थानों के जरिए पढ़ाई से न केवल विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को पनपाने का बड़ा कारण भी बनता है। यह किसी से छिपा नहीं कि शिक्षा समाज को योग्य और समर्थ बनाने की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के परिसर एक परिपक्व और सृजनशील मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला होते हैं। वहां विद्यार्थी जीवन मूल्यों की दीक्षा पाता है। उसके व्यक्तित्व की बनावट भी बहुत हद तक वहीं होती है। चूंकि भारत में शिक्षा ऐतिहासिक रूप से अनेक चुनौतियों से घिरी रही है, इसलिए उसकी समस्याएं इकट्ठी होती गई हैं। भारतीय राजनीति शिक्षा के प्रति अलग-अलग नजरिये से संवेदनशील रही है। फलतः शिक्षा में प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से राजनीतिक प्रयोग होते रहे हैं। चूंकि शिक्षा समाज के वर्तमान और भविष्य, दोनों से जुड़ी रहती है, इसलिए उसमें राजनीतिक दिलचस्पी स्वाभाविक है। आजादी के बाद सेक्युलर दृष्टि शिक्षा की आधारशिला बनी, जिसने बहुत कुछ जो भारतीय था, उसे भुला दिया, बहिष्कृत कर दिया या घटा-बढ़ाकर विकृत रूप में शामिल किया। सरकार को चाहिए कि स्कूली शिक्षा को सशक्त किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण पर निवेश होना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को स्कूली कोर्स से जोड़ा जाए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास व समाज के लिए योगदान होना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को पश्चिमी दुनिया के अनुकूल बनाने और उसी के पैमाने पर चलाने का उद्यम चलता रहा। औपनिवेशिक काल में ज्ञान और संस्कृति के एकल प्रतिमान के रूप में जो अंग्रेजियत स्थापित हुई, वह वर्चस्व बनाती गई। स्वतंत्र भारत में अपनाई गई शिक्षा की नीतियां, योजनाएं, प्रविधान और उनका कार्यान्वयन प्रायः पुरानी लीक पर ही होता रहा। स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए पश्चिमी माडल से हम उबर नहीं पाए हैं। थोड़ा बहुत हेरफेर कर काम चलाते रहे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय शिक्षा के समग्र, समावेशी और स्वायत्त स्वरूप विकसित करने की बात धरी की धरी रह गई। लोकहित के व्यापक लक्ष्यों के लिए समानता और समता जरूरी है, पर भारत में शिक्षा कई तरह से विभेदकारी होती जा रही है। आज सरकारी, अर्ध-सरकारी और स्वचित्तपोषित संस्थाएं चल रही हैं। उनमें फीस, प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा के तौर-तरीके भी बemeल हैं। बच्चे को पढ़ाना अभिभावकों के लिए बरसों बरस चलने वाले संघर्ष बन गया है।

सहयोग के नए दौर में भारत और फ्रांस

फ्रांस की अध्यक्षता में इस साल हुए जी-7 समिट के नाकाम हो जाने की कई वजहें थीं। कई झगड़े, समुद्री व्यापार के रास्तों में रुकावट, ऊर्जा संकट, महामारी का फैलना, ग्लोबल मैक्रो-इकोनमिक असंतुलन, मदद के तरीकों में रुकावट और विभाजित विश्व की वजह से दांव पर बहुत कुछ लगा था। फिर भी 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन में जो हुआ, वह एक साथ आने का दुर्लभ मौका था। नेताओं के बीच सहयोग से बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस वादे मुमकिन हो पाए। यह सफलता न केवल जी-7 सदस्य देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका) के बीच, बल्कि जी-7 प्लस के जरूरी सहयोगी देशों-खासकर भारत और साथ ही ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया के साथ भी करीबी तालमेल का नतीजा थी। यूक्रेन, यूएई और कतर को भी अपनी राय देने के लिए नेताओं के समिट में बुलाया गया था। इस अनोखे जी-7 प्लस फॉर्मेट के जरिये फ्रांस की अध्यक्षता ने न केवल समिट में, बल्कि समिट से पहले तैयारी की प्रक्रिया के दौरान भी पहली बार भारत और सहयोगी देशों के अनुभव और विजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारत और फ्रांस के जी-7 के साथ रिश्ते बहुत पुराने हैं। जी-7 के साथ भारत का जुड़ाव 2003 में फ्रांस के न्योते पर एवियन में शुरू हुआ था। इस साल समिट में भारत की 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार सातवीं भागीदारी थी, जब फ्रांस ने अपनी पिछली अध्यक्षता के दौरान भारत को जी-7 बियारिट्ज समिट में बुलाया था। इस साल जी-7 प्लस में भारत का योगदान सभी मामलों में अहम था, खासकर स्वास्थ्य और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी ग्लोबल चुनौतियों पर। जी-7 नेताओं ने सर्वसम्मति से नौ घोषणाओं को अपनाया और कई को सहयोगी देशों का समर्थन मिला। ये हमारी बड़ी साझा सफलताएं थीं। जी-7 ने यूक्रेन



की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, रक्षा और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के समर्थन के मामले में मजबूत एकजुटता और संकल्प दिखाया। हमने हाल के महीनों में युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साहस की तारीफ की और उस नई गति पर जोर दिया, जिससे इस आक्रामक युद्ध का न्यायपूर्ण और अंतिम समाधान निकल सकता है। हमने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया और होर्मुज से बिना किसी रोक-टोक या टोल के आने-जाने के अधिकार को फिर से दोहराया। हमने लेबनान में तुरंत और मजबूत युद्धविराम की भी पुरजोर मांग की, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। मैक्रो-इकोनमिक असंतुलन से निपटने के लिए नेताओं ने संतुलित, टिकाऊ और मजबूत विकास का समर्थन किया। उन्होंने माना कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए, उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करते हुए, और भविष्य के व्यापार युद्धों और वित्तीय संकटों से बचते हुए आर्थिक नीतियों में सहयोग और समन्वय सभी के हित में है। चूंकि इस बड़ी चुनौती के समाधान में सभी की भागीदारी जरूरी है, इसलिए फ्रांसीसी अध्यक्षता ने चीन के साथ रचनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दी। चीन ने जी-7 एवियन शिखर सम्मेलन से पहले विकास के लिए एक अभूतपूर्व वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया, जो 20 वर्षों में पहली बार हुआ। डिजिटल तकनीक और एआई पर, इंडिया एआई इमैक्ट समिट के बाद जी-7 प्लस नेताओं ने बच्चों की आनलाइन सुरक्षा को बेहतर बनाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। हम एआई सुरक्षा जोखिमों का

सामना कर रहे लोकतंत्रों के बीच सहयोग के लिए एक साझा मंच बनाने की योजना बना रहे हैं ताकि साझा मानक स्थापित किए जा सकें। जी-7 प्लस सदस्य सुरक्षित और लाभकारी एआई के इस्तेमाल को तेज करने के लिए प्रमुख कंपनियों के साथ काम करेंगे। इसमें भारत की सर्वम एआई भी शामिल है। स्वास्थ्य मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। जी-7 नेताओं और सहयोगी देशों ने इबोला वायरस से प्रभावित लोगों के प्रति समर्थन का संदेश दिया और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के अनुरूप एक अरब डालर से अधिक की धनराशि देने का वादा किया। कैंसर से निपटने पर पहली बार जी-7 का बयान भी जारी हुआ। नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता को दोहराया, विशेष रूप से मानव विकास और सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा कार्यान्वित 'फाइनेंस इन कामन' इस दिशा में उपयोगी भूमिका निभाएगा। सभी नेता महत्वपूर्ण खनिजों पर अपनी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर सहमत हुए। इस उद्देश्य के लिए कुल 195 ठोस सहयोग परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें 64 अरब यूरो का संयुक्त निवेश शामिल है। सुरक्षा मुद्दों पर हमने क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और प्रवासियों की तस्करी से निपटने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जी-7 अध्यक्षता अभी समाप्त नहीं हुई है। इन विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए 2026 में कई मंत्री-स्तरीय और कार्य-समूह बैठकें होंगी, जिनमें भारत की अहम भूमिका होगी। ब्रिक्स चेयरमैन के तौर पर भारत और जी20 के चेयरमैन के तौर पर अमेरिका, दोनों ही इन चुनौतियों पर ठोस पहल को आगे बढ़ाने और दुनिया के बीच की दूरियों को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह ऐसे समय में हो रहा है जब सभी की ओर से तालमेल और रचनात्मक जुड़ाव पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।

नीली रोशनी का विभाजन: आज के माता-पिता लड़ाई क्यों छोड़ रहे हैं?

रात के एक या दो बजे हैं। घर की सभी लाइटें बंद हैं, शयनकक्ष के दरवाजे के नीचे से धुंधली, नीली चमक निकल रही है। एक माँ आधी रात को जाग जाती है। वह पानी पीने के लिए उठती है और लापरवाही से बच्चे के कमरे में झाँकती है। वहाँ वे बैठे हैं, उनके हाथ में एक मोबाइल फोन है और हेडफोन मजबूती से अपनी जगह पर रखे हुए हैं। स्क्रीन पर कुछ चल रहा है। कुछ खेल जोरों से चल रहा है। समय ने अपना अर्थ पूरी तरह खो दिया है। यह दृश्य आज अनगिनत घरों में हर रात चलता है। अगले दिन, चक्र जारी रहता है: दोपहर ग्यारह या बारह बजे तक सोना, बार-बार कुहनी मारने के बाद ही जागना। जब वे अंततः बिस्तर से उठते हैं, तो एक हाथ में फोन होता है और दूसरे हाथ में कॉफी का कप होता है। शरीर तकनीकी रूप से जागृत है, लेकिन दिन की प्राकृतिक लय पूरी तरह से खो गई है। पूरी रात जागना, दोपहर में उठना और सुबह होने तक लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर घूरते रहना अब सामान्य बात हो गई है। समय बदलता है, प्रौद्योगिकी विकसित होती है और जीवनशैली अनुकूल होती है। ये सब स्वीकार्य है। लेकिन मानव शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं अपरिवर्तित रहती हैं। शरीर को शारीरिक आराम की

आवश्यकता होती है। दिमाग को गहरी, आरामदायक नींद की जरूरत होती है। आँखों को अँधेरे की जरूरत होती है, और मस्तिष्क को पुनर्जीवित होने और पुनः अंशांकित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। हालाँकि, आज की पीढ़ी अपने ही जीव विज्ञान से प्रतिस्पर्धा कर रही है। उनका मानना है कि पर्याप्त प्रौद्योगिकी और डेटा के साथ, वे मानव शरीर क्रिया विज्ञान को मात दे सकते हैं और जैव-लय को दरकिनार कर सकते हैं। आज के किशोर रात को दिन और दिन को रात मानने लगे हैं। माता-पिता के रूप में, हम ऐसा होते हुए देखते हैं। सबसे पहले, हम बोलते हैं। हम उन्हें प्यार से सलाह देते हैं। फिर, हम परिणामों को समझाने का प्रयास करते हैं। हम खुद को दोहराते हैं। कभी-कभी हमें गुस्सा आता है; कभी-कभी हम विनती करते हैं। लेकिन आज के बच्चों के पास पहले से दर्ज प्रतिक्रियाओं का एक भंडार है जो जवाब देने के लिए तैयार है: "हमारी पीढ़ी का जीवन अलग है।" बार-बार बर्खास्तगी की बातें सुनकर, माता-पिता अंततः चुप हो जाते हैं। लेकिन उनका मन शांत नहीं है। वे अनुभव से जानते हैं कि यदि आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो अंततः आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीस या पच्चीस की उम्र



में आप अजेय महसूस करते हैं। लेकिन पुरानी नींद की कमी, अनियमित दिनचर्या, शारीरिक गतिविधि की कमी और अत्यधिक स्क्रीन समय के छोटे बीज चुपचाप बोए जा रहे हैं। समय के साथ, वे बीज विकसित होते हैं और बढ़ते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। एकाग्रता कम हो जाती है। रिश्तों में संचार कम हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है और सबसे बुरी बात यह है कि जीवन की साधारण खुशियाँ गायब होने लगती हैं। फिर भी, माता-पिता के लिए, सबसे दर्दनाक हिस्सा इन परिणामों को न देखना है; यह पीड़ादायक अहसास है कि वे अब अपने बच्चों तक नहीं पहुँच सकते।

माता-पिता अपने बच्चों के दुश्मन नहीं हैं; वे अपने सपनों के सबसे सच्चे गवाह हैं। वे अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करने वाले पहले व्यक्ति हैं और जब विफलता आती है तो वे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। वे बीमारी के दौरान पूरी रात जागते हैं और अपनी जीत से ज्यादा अपने बच्चों की जीत का जश्न मनाते हैं। जब कोई माता-पिता अपने बच्चे को पूरी रात जागने से मना करते हैं, तो यह नियंत्रण की इच्छा से नहीं आता है। यह प्यार से आता है। यह अनुभव, देखभाल और एक भयंकर, निस्वार्थ भय से आता है: "मेरे बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए।" लेकिन जब अंतहीन बातचीत के

बावजूद कुछ नहीं बदलता, तो माता-पिता धीरे-धीरे चुप्पी साध लेते हैं। बच्चे अक्सर इसे उदासीनता समझ लेते हैं, सोचते हैं कि उनके माता-पिता को अब कोई परवाह नहीं है। हकीकत में, वे गहराई से परवाह करते हैं। उन्हें बस यह एहसास हो गया है कि शब्दों की शक्ति समाप्त हो गई है, और जीवन को ही शिक्षक बनना होगा। ये खामोशी हार नहीं है; यह एक दुखद स्वीकृति है। एक भारी मजबूरी। जिस दिन माता-पिता बहस करना बंद कर देते हैं, उनकी चिंताएँ खत्म नहीं होतीं, बल्कि और भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि माता-पिता बनना जीवन भर की सजा है। चिंता की प्रकृति उम्र के साथ बदलती रहती है, लेकिन यह वास्तव में कभी खत्म नहीं होती। इसलिए, आज की युवा पीढ़ी से मेरा एक अनुरोध है: आपको अपने माता-पिता की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप हर राय से सहमत हों। अपने स्वयं के विचार रखें, अपने निर्णय स्वयं लें, और अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिएं। लेकिन कभी-कभार, उनकी नोक-झोंक के पीछे छिपे प्यार को सुनने की कोशिश करें। क्योंकि जीवन में बाद में एक समय ऐसा आएगा जब आपको अचानक हर चीज का महत्व समझ में आ जाएगा, ऐसा वे आज कह रहे हैं।

पूरे महाराष्ट्र में मौनसून सक्रिय

■ मुंबई में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा ■ सड़कों पर जलभराव ■ ट्रेन लेट और विमान सेवा भी प्रभावित



मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। महानगर और उसके आसपास के उपनगरीय इलाकों में बुधवार (1 जुलाई 2026) सुबह तक पिछले 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से अधिक मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। इस आफत की बारिश के कारण मुंबई के कई निचले इलाकों सहित अंधेरी सबवे में भारी जलभराव हो गया है, जिससे यातायात को डायवर्ट करना पड़ा है। बारिश अब भी लगातार हो रही है। जिससे लोगों में 26 जुलाई वाली दहशत पैदा हो गई है। भारी वर्षा का सीधा असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों और हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। सड़कों पर समंदर

जैसा नजारा होने के कारण जगह-जगह लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़क और रेल यातायात के साथ-साथ हवाई यातायात भी इस मूसलाधार बारिश की चपेट में आ गया है। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता काफी कम हो जाने के कारण विमानों के संचालन में भारी बाधा आ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर कई उड़ानों को नजदीकी हवाई अड्डों पर डायवर्ट किया गया है, जबकि दर्जनों उड़ानें देरी से उड़ान भर रही हैं। जमीन पर हालात ये हैं कि प्रमुख बाजारों और गलियों में पानी घुसने से व्यापारियों का लाखों का सामान खराब हो गया है। सड़कों पर जलभराव के चलते कई गाड़ियां और बाइक बीच रास्ते में

ही बंद हो गई, जिन्हें धक्का लगाते लोग नजर आए। प्रशासन ने नागरिकों को आपात स्थिति को छोड़कर घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। भिवंडी तालुका में कई घंटों से लगातार हो रही बारिश का असर मुंबई-नासिक हाईवे पर साफ दिखाई दे रहा है। अधूरे निर्माण कार्य, सड़क पर बने गड्ढों और जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। राजनोली, पिंपलनेर, मानकोली से लेकर खारीगांव टोल नाका तक मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।

प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

■ लगातार बारिश और हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस, बीएमसी और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले इलाकों में जोखिम न लेने और मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं।

डांस बार के नियम होंगे सख्त

मुंबई पुलिस अधिनियम में होगा बदलाव



मुख्यमंत्री
फडणवीस
ने पुलिस के
खोले हाथ

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार डांस बारों को लेकर कानून और सख्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि राज्य सरकार चल रहे मानसून सत्र के दौरान मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। क्योंकि कुछ डांस बार संचालक मौजूदा कानून की कमियों का फायदा उठाकर दूसरे नियमों के तहत लाइसेंस ले लेते हैं और डांस बार से जुड़े कड़े नियमों से बच जाते हैं। फडणवीस ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के प्रदर्शन आयोजित करने वाले प्रतिष्ठान केवल डांस बार को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त कर सकें, जहां सख्त शर्तें निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा, 'मौजूदा कानून में मौजूद खामी का फायदा उठाते हुए

संचालक डांस बार कानून के बजाय किसी अन्य कानून के तहत लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। हम इसमें संशोधन ला रहे हैं ताकि ऐसे लाइसेंस केवल संशोधित मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत ही जारी किए जा सकें। वे खामियां ढूंढते रहते हैं और हम उन्हें दूर करते रहते हैं।' उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार विधि एवं न्याय विभाग के परामर्श से, नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने के लिए कानून में संशोधन के प्रस्ताव की भी जांच कर रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें बहुत बारीक रेखा होती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में गलत काम करने के दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, हालांकि उनके पास अधिकारियों की सटीक संख्या नहीं है। चर्चा के दौरान, सदस्यों ने भिवंडी के कुछ हिस्सों में डांस बार की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही आरोप लगाया कि वे अपराध के केंद्र बन गए हैं, सरकार से नियमों को सख्त करने का आग्रह किया।

नवी मुंबई मनपा के बेड़े में शामिल होंगी 150 नई सीएनजी बसें

नवी मुंबई: नवी मुंबई मनपा परिवहन उपक्रम में सीएनजी से चलने वाली 150 नई बसें एक साल के अंदर मनपा के बेड़े में शामिल की जाएंगी। इनमें से 30 बसें पहले फेज में शामिल की जा चुकी हैं। विश्वास व्यक्त किया गया है कि इससे यात्रियों को बेहतर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल सकेगी। इलेक्ट्रिक बसों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए नवी मुंबई महानगर परिवहन उपक्रम ने सीएनजी बसों को खरीदने का निर्णय लिया है। नवी मुंबई मनपा के ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी एनएमएमटी के बेड़े में अभी 350 बसें हैं। ये बसें नवी मुंबई से पनवेल, उरण, खोपोली, कल्याण डोंबिवली, बोरीवली मंत्रालय तक चल रही हैं। एनएमएमटी बसों में महिलाओं से आधी टिकट ली जा रही है। अभी, पहले फेज में ये 30 बसें ट्रांसपोर्ट सेवा में आ गई हैं। बाकी



की बसें धीरे धीरे आती रहेंगी। अब तक जो बसें आ गई हैं, वे घनसोली ट्रांसपोर्ट डिपो में खड़ी हैं। बीस बसें अगले महीने आएंगी। यह जानकारी ट्रांसपोर्ट सूत्रों से मिली है। ये सभी बसें ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खुद खरीदी हैं। इसलिए इन बसों से होने वाली सारी इनकम ट्रांसपोर्ट के अकाउंट में जमा होगी। इसलिए, कंपनी ने भरोसा जताया है कि यह बस ट्रांसपोर्ट के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा, पैसेंजर भी इस बस से अच्छी बस सर्विस का मजा ले पाएंगे।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने सौंपी 300 परिवारों को घरों की चाबियां

ठाणे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 'घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह प्रेम, अपनापन, खुशियों और परिवार के सपनों का संसार होता है।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। ठाणे के माजिवडा सर्कल स्थित साईनाथ नगर की जय भवानी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के सदस्यों को नए घरों की चाबियां सौंपने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिंदे ने यह बात कही। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी परिवार के अपने घर का सपना साकार होते देखना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का क्षण होता है। उपमुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि नगरसर्वक से लेकर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष



के नेता और अब उपमुख्यमंत्री तक की उनकी यात्रा ठाणे की जनता के विश्वास और आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इसी विश्वास के साथ सरकार राज्य के हर पात्र नागरिक को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। **डेवलपर की सराहना :** डीसीएम शिंदे ने कहा कि गृहनिर्माण मंत्री का दायित्व संभालने के बाद राज्यभर में वर्षों से लंबित पुनर्विकास एवं आवास परियोजनाओं को गति देने का

निर्णय लिया गया है। परियोजनाओं में आने वाली प्रशासनिक एवं तकनीकी बाधाओं को दूर कर उन्हें शीघ्र पूरा किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस हाउसिंग सोसायटी के विकास करने वाले धरम कटारिया की सराहना करते हुए कहा कि अनेक अड़चने हुईं लेकिन उनको दूर करते हुए विकासक ने आखिरकार वादा पूरा किया।

मंत्री आशिष शेलार ने कहा

MPSC परीक्षा अब होगी कंप्यूटर आधारित, निजीकरण नहीं होगा

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। विधान परिषद में सामान्य प्रशासन मंत्री आशिष शेलार ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का उद्देश्य समय पर भर्ती पूरी करना है और परीक्षा का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन मंत्री आशिष शेलार ने बताया कि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया का दायरा पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है। पहले आयोग के माध्यम से हर वर्ष लगभग 7 से 7.5 हजार पदों पर ही भर्ती होती थी, लेकिन अब विभिन्न विभागों में रिक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण यह आंकड़ा 50 से 60 हजार पदों तक पहुंचने की संभावना है। इतनी



बड़ी भर्ती प्रक्रिया को पारंपरिक ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली के जरिए समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसी कारण सरकार ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि सीबीटी प्रणाली से परीक्षा का आयोजन अधिक तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया भी कम समय में पूरी होगी, जिससे परिणाम जल्दी घोषित किए जा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि जिस वर्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, उसी वर्ष परीक्षा आयोजित

पारदर्शिता और सुविधा पर जोर

■ राज्य सरकार उम्मीदवारों को उत्तरपत्रिका उपलब्ध कराएगी और अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा होने पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति ने भी सीबीटी प्रणाली की सिफारिश की है। शेलार ने कहा कि परीक्षा संचालन के लिए टीसीएस जैसी संस्थाओं की तकनीकी सेवाएं ली जा सकती हैं, लेकिन एमपीएससी परीक्षाओं का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

कर परिणाम घोषित किए जाएं और सफल अभ्यर्थियों को समयबद्ध तरीके से नियुक्ति भी प्रदान की जाए।

पेज-1 का शेष

जनजातीय युवाओं को बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू...

इससे जनजातीय समाज की आजीविका मजबूत होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित हो रहे भारत में सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए आधुनिक विज्ञान के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय उत्तरी आंध्र प्रदेश के जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए 'साइंस एंड टेक्नोलॉजी हब' का संचालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जनजातीय कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा ऊर्जा संरक्षण जैसे विषयों पर अकादमिक और जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जो

उन्हें भविष्य के लिए नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है।

NEET और JEE एंट्रेंस एग्जाम में 12वीं बोर्ड का मिल सकता है 50% वेटेज

अभी कैसे होता है एग्जाम ? : मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट मौजूदा समय में स्कोर के आधार पर होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य होने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड एग्जाम में एक निश्चित प्रतिशत अंक लाने होते हैं। शिक्षा मंत्रालय की नौ-सदस्यीय समिति इन सुधारों पर विचार कर रही है। इस समिति का गठन पिछले साल छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए, डमी स्कूलों के प्रसार और अहम एंट्रेंस टेस्ट में निष्पक्षता की जांच करने के लिए किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के पैनल की अंतिम रिपोर्ट आने वाले हफ्तों में सरकार को सौंपी जा सकती है। समिति ने एंट्रेंस टेस्ट को स्कूल के सिलेबस से बेहतर ढंग से जोड़ने की भी सिफारिश की है।

वाढवण
बंदरगाह से
बुलेट ट्रेन
तक

पालघर की 5 मेगा परियोजनाओं को सीएम फडणवीस ने दी रफ्तार



मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर जिले का दौरा कर महाराष्ट्र के विकास के लिए मील का पत्थर मानी जाने वाली पांच प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं में वाढवण बंदरगाह, बुलेट ट्रेन, नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नारिंगी खाड़ी पुल और उत्तन-विरार समुद्री सेतु शामिल हैं। प्रशासनिक तत्परता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं, ताकि मुंबई महानगर क्षेत्र को एक महा-आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा सके। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को आने वाले वर्षों में परिवहन और बुनियादी ढांचे का एक अभूतपूर्व मल्टी-इन्फ्रा बूस्ट मिलने जा रहा है। पालघर जिले में आकार ले रही ये पांच मेगा परियोजनाएं एमएमआर की कनेक्टिविटी की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देगी। नए बंदरगाह, हवाई अड्डे, हाई-स्पीड रेल और समुद्री सेतुओं के इस एकीकृत नेटवर्क से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारी बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी वृद्धि होगी। इन ढांचागत बदलावों के पूरा होने से मुख्य मुंबई शहर पर से जनसंख्या और यातायात का भारी दबाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा।

कनेक्टिविटी होगी हाई-स्पीड

■ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ रहे यात्री और माल ढुलाई के दबाव को कम करने के लिए पालघर में नया वाढवण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। यह हवाई अड्डा विशिष्ट माल ढुलाई गलियारे (डीएफसीसी), बुलेट ट्रेन और मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे के करीब होने के कारण एमएमआर का तीसरा बड़ा विमानन केंद्र बन जाएगा, इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत बोईसर स्टेशन के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इस स्टेशन के बनने से मुंबई के बीकेसी (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स) से पालघर तक की दूरी महज कुछ मिनटों में सिमट जाएगी।

एमएमआर का होगा सर्वांगीण विकास

■ सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए दो बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। लगभग 850 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 4.10 किलोमीटर लंबा नारिंगी खाड़ी पुल वसई-विरार को सफाले, पालघर और बोईसर से सीधे जोड़ेगा। इससे यात्रा की दूरी 40 किलोमीटर और समय लगभग 45 मिनट कम हो जाएगा, इसके अलावा, लगभग 58,754.51 करोड़ रुपये की लागत वाला छह लेन का उत्तन-विरार समुद्री सेतु दक्षिण मुंबई से अहमदाबाद तक के सफर को बेहद तेज और सुरक्षित बनाएगा, जिससे एमएमआर के भीतर श्रम गतिशीलता बहुत आसान हो जाएगी।

बेस्ट की स्मार्ट मीटर लाने की योजना



मुंबई: बेस्ट अगले तीन सालों में अपने बेड़े में 5,000 खुद की बसें शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मकसद धीरे-धीरे वेट-लीज मॉडल पर निर्भरता कम करना और शहर के बस बेड़े पर ऑपरेशनल कंट्रोल को मजबूत करना है। इस प्लान की डिटेल्स कंपनी की जनरल मैनेजर सोनिया सेठी ने नगर निगम की स्टैंडिंग कमिटी को दी। पिछले हफ्ते जब नगर निगम कमिटी ने कंपनी के लिए 1,000 करोड़ रुपये के मदद पैकेज को मंजूरी दी, तो सेठी ने कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और आगे के रास्ते पर एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कमिटी को यह भी बताया कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक मुंबई को लगभग 10,000 बसों की जरूरत है। सेठी ने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक बेस्ट की कुल देनदारियां 23,296 करोड़ रुपये थीं। जहां बिजली विभाग 2025-26 में 115 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ मुनाफे

में रहा, वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग को 1,805 करोड़ रुपये का घाटा होता रहा। उन्होंने पुराने कर्मचारियों के 1,751 करोड़ रुपये के पेंडिंग रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी एरियर को क्लियर करने का प्लान पेश किया। हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग में दिए गए निर्देशों के अनुसार, बेस्ट का लक्ष्य मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इन एरियर को क्लियर करना है। प्रेजेंटेशन में यह भी पता चला कि इएरल का इरादा एडवर्टाईजमेंट, बस इंफ्रास्ट्रक्चर के कमर्शियल इस्तेमाल, एच चाजिंग स्टेशन और दूसरे मोनेटाइजेशन उपायों के जरिए नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने का है। इसके अलावा, पावर डिपार्टमेंट बिलिंग एफिशिएंसी को बेहतर बनाने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने और पावर चोरी को रोकने के लिए 5,50,000 स्मार्ट मीटर लगाने का प्लान बना रहा है।

वाधवान पोर्ट के लिए 208 मैंग्रोव काटे जाएंगे



मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर जिले में बड़े वाधवन पोर्ट को नेशनल हाईवे नंबर 48 से जोड़ने के लिए एक एक्सेस रोड बनाने के लिए कोस्टल फ्लडप्लेन में 208 मैंग्रोव पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैंग्रोव की सही सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट के पहले दिए गए परमानेंट ऑर्डर के मुताबिक मैंग्रोव को काटने के लिए एक पिटीशन के जरिए परमिशन मांगी थी। नेशनल हाईवे

अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाधवन पोर्ट को नेशनल हाईवे नंबर 48 से जोड़ने के लिए आठ-लेन कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाने के लिए जरूरी एनवायरनमेंटल, कोस्टल रेगुलेशन एरिया और फॉरेस्ट क्लीयरेंस ले ली थी। इसने कम्पेनसेटरी अफॉरेस्टेशन की शर्तें भी पूरी कर ली थीं। इसके मुताबिक, प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रहे 208 मैंग्रोव पेड़ों को काटने के लिए फाइनल अप्रूवल मांगा गया था।

NMMC ने घनसोली में 89.62 लाख के ड्रेनेज और फुटपाथ प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

गौरव सिंह/ नवी मुंबई

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMMC) की स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी पिछली मीटिंग में मंजूर किए गए सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की एक सीरीज के हिस्से के तौर पर, घनसोली के शांतिनगर इलाके में स्टॉर्मवॉटर ड्रेन और फुटपाथ बनाने के लिए 89.62 लाख के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में 371 मीटर लंबा ड्रेन और 356 मीटर लंबा, चार मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाना शामिल है, ताकि इलाके में ड्रेनेज बेहतर हो सके और पैदल चलने वालों का आना-जाना आसान हो सके। म्युनिसिपल कमिशनर डॉ. कैलाश शिंदे के तहत सिविक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जमा किए गए इन प्रस्तावों को चेयरमैन अशोक भाऊसो पाटिल की अध्यक्षता में हुई स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग में एकमत से मंजूरी दे दी गई। मंजूर किए गए दूसरे प्रोजेक्ट्स में, कमिटी ने



घनसोली के बलराम वाडी में 130 मीटर लंबे ड्रेन के बनाने के लिए INR 31.12 लाख मंजूर किए, ताकि सही ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से हुए वॉटरलॉगिंग को ठीक किया जा सके। कमिटी ने नेरुल के सेक्टर 8 के कॉन्डोमिनियम एरिया में खराब सीवर लाइनों और चैंबर को बदलने और सुधारने के लिए INR 63.05 लाख भी मंजूर किए, जहाँ रहने वालों ने बार-बार सीवेज ब्लॉकेज की शिकायत की है। वाशी में, सेक्टर 7 में आई-बाबा गार्डन के डेवलपमेंट के लिए INR

25.90 लाख मंजूर किए गए, जबकि सेक्टर 6 में ज्ञान कलश गार्डन के ब्यूटीफिकेशन के लिए 30.59 लाख मंजूर किए गए। इसके अलावा, CBD बेलापुर में राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कंपाउंड वॉल की मरम्मत के लिए 29.26 लाख मंजूर किए गए। सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, इन प्रोजेक्ट्स का मकसद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, मनोरंजन की जगहों को बढ़ाना और नवी मुंबई में लंबे समय से पेंडिंग सिविक मुद्दों को सुलझाना है।

Result Guarantee Above 90% or Money Back

If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things

Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy
MUMBAIHOME & PRIVATE TUTORING

1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / WJEC / State Boards
XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET
Engg, Degree, Diploma, B.Com, B.Sc., BMS,
MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking

Any Class Home Tuitions Across Mumbai
Get Admission in MBBS
NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs
(Inc. Food Acc.)

ADMISSIONS OPEN
Branches: Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Badar - Borivali - Vihar
Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur

Home Tuitions Benefits
1. 100% get personal attention from class to class.
2. 100% get personal attention from class to class.
3. 100% get personal attention from class to class.

4. No Time Wasting in class time.
5. Have efficiency 10 times more than classes in schools.
6. Class Time is per student convenience in classes as per their time.

Contact: 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153
<https://www.mumbaihometutors.com>

**PRIME KEYS
PROPERTIES**

Beyond Dreams

BUY | SELL | RENT

FLATS • SHOPS • BUNGALOWS

LANDS • REDEVELOPMENT

- ✓ Trusted Property Consultant
- ✓ Residential & Commercial Deals
- ✓ Best Market Price Assistance

Contact:

+91 9167378057

Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC

Ambernath (W), Maharashtra

Nursing Home Reg. No.: THN-C274*

FACILITIES AVAILABLE

- ✓ 24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support
- ✓ Diabetology & Advanced Diabetic Care
- ✓ Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)
- ✓ Cardiology Checkup & ECG Facility
- ✓ General Medicine Consultation
- ✓ Vaccination & Immunization Services
- ✓ Minor Surgical Procedures
- ✓ OPD & IPD Care Available
- ✓ Complete Health Checkups

24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE

+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambernath West, Thane

Woolen Chawl OPD: 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care: 8149477110

DR. ZUBER S. SHAH

M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)

Cert. in Diabetology & Emergency Medicine



■ डॉ. आशीष मिश्रा श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

बा भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक आदत और दिन की शुरुआत का अहम हिस्सा बन चुकी है। सुबह उठते ही चाय पीना, ऑफिस में ब्रेक के दौरान

अगर एक महीने के लिए चाय छोड़ दें तो शरीर में दिखेंगे ये बड़े बदलाव

चाय लेना और शाम को दोस्तों के साथ चाय का आनंद लेना लगभग हर किसी की दिनचर्या में शामिल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक महीने के लिए चाय पीना छोड़ दें तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा? चाय में मौजूद कैफीन और चीनी अधिक मात्रा में लेने पर नींद, पाचन और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। कई लोग बिना चाय के दिन की शुरुआत नहीं कर पाते, लेकिन इसे छोड़ने से शरीर में कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी चाय के आदी हैं, तो यह जानना जरूरी है कि 30 दिनों तक चाय छोड़ने पर शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं और यह आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है।

तनाव और चिंता में कमी

■ कैफीन अधिक मात्रा में लेने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं, जिससे चिंता, बेचैनी और घबराहट महसूस हो सकती है।
■ चाय छोड़ने के बाद दिमाग अधिक शांत रहता है और मूड स्विंग्स में भी कमी देखने को मिलती है।
■ इससे मानसिक स्थिरता और फोकस बेहतर होता है।

हार्ट हेल्थ में सुधार

■ अत्यधिक कैफीन का सेवन कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को प्रभावित कर सकता है।
■ चाय की मात्रा कम या बंद करने से हार्ट पर दबाव कम होता है और ब्लड सुकुर्लेशन बेहतर हो सकता है।
■ यह लंबे समय में दिल की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।

नींद की गुणवत्ता में सुधार

■ चाय में मौजूद कैफीन एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जो दिमाग को एक्टिव रखता है और नींद आने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है।
■ जब आप चाय पीना बंद करते हैं, तो शरीर में कैफीन का असर धीरे-धीरे कम होने लगता है।
■ इससे नींद जल्दी आती है और नींद की गहराई भी बेहतर होती है।
■ कई लोग बताते हैं कि चाय छोड़ने के बाद रात में बार-बार नींद टूटने की समस्या भी कम हो जाती है।

एसिडिटी और गैस में राहत

■ ज्यादा चाय पीने से पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे एसिडिटी, जलन और गैस की समस्या हो सकती है।
■ खासकर खाली पेट चाय पीना पाचन तंत्र पर असर डालता है।
■ जब आप चाय छोड़ते हैं, तो पेट का एसिड बैलेंस बेहतर होता है और पाचन प्रक्रिया धीरे-धीरे सामान्य होने लगती है।
■ इससे पेट हल्का और आरामदायक महसूस होता है।



'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

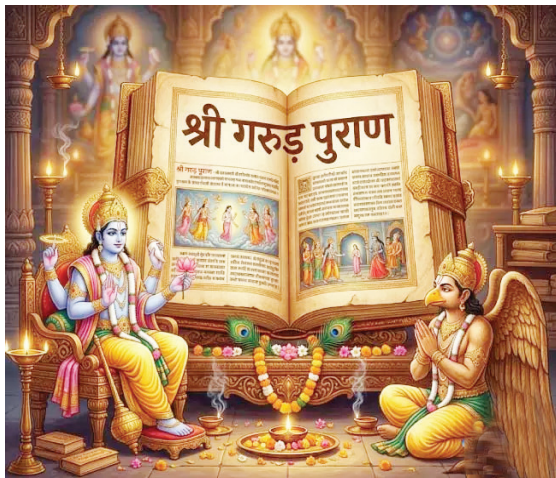
गरुड़ पुराण में बताए गए अहम नियम

गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा से जुड़े कई गहरे संदेश दिए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से पूर्वजों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूर्वजों की शांति और कृपा के लिए सदाचार और सही आचरण बेहद जरूरी माना गया है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कार्यों से बचने की सलाह दी गई है जो पितृ दोष या नकारात्मक परिणाम का कारण बन सकते हैं।

1. झूठ बोलना और धोखा देना

गरुड़ पुराण के अनुसार, झूठ बोलना और किसी को धोखा देना गंभीर पाप माना गया है। ऐसा करने से न केवल व्यक्ति के कर्म



खराब होते हैं, बल्कि पूर्वज भी अप्रसन्न हो सकते हैं। सत्य और ईमानदारी को जीवन का मूल आधार माना गया है।

2. बुजुर्गों और माता-पिता का अपमान
ग्रंथ में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता-पिता, बुजुर्गों या गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे कर्मों को पूर्वजों के प्रति अपमान माना जाता है, जिससे उनकी कृपा

कम हो सकती है। सम्मान और सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है।

3. दान और परोपकार से दूर रहना

गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद नहीं करता और केवल अपने स्वार्थ में लिप्त रहता है, उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होते। दान और परोपकार को पुण्य कर्म माना गया है, जो पूर्वजों की आत्मा को संतोष देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन कार्यों से बचकर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है और पूर्वजों की कृपा प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत गलत आचरण जीवन में बाधाएं और कठिनाइयों का कारण बन सकता है। हालांकि, आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये शिक्षाएं नैतिकता और अच्छे व्यवहार पर आधारित हैं, जो समाज में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करती हैं।

कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी का महत्व

आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के कृष्णपिंगल स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन को कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वालों को हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी 3 जुलाई 2026 को सुबह 11.20 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 जुलाई 2026 को दोपहर 12.39 पर समाप्त होगी। ये व्रत चंद्रमा की पूजा से जुड़ा है और पंचांग अनुसार चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा का समय 3 जुलाई को इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। चंद्र पूजन के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। 3 जुलाई को कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी तिथि का चंद्रमा रात 09.53 पर उदय होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन भद्रा सुबह में 05:28 से सुबह 11:20, इसका वास पाताल



लोक में है। इसमें पूजा पाठ हो सकती है। गणपति पूजन में भद्रा अवरोध नहीं बनेगी। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन व्रती प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद पापनाशक श्री गणेश जी की पूजा करें। पूजा के दौरान श्री गणेशजी को तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा और चंदन अर्पित करें तथा मोदक का भोग लगाएं। आरती करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें।

पेज-1 का शेष

भारत-जापान के बीच रक्षा क्षेत्र की पहली सह-विकास परियोजना पर हुआ समझौता...
द्विपक्षीय वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक का विवरण साझा करते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "विश्वास, साझा मूल्यों और रणनीतिक अभिसरण पर आधारित साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद हाउस में जापान के प्रधान मंत्री साने ताकाची का गर्मजोशी से स्वागत किया।" एक अन्य पोस्ट में, विदेश मंत्रालय ने रिश्ते को "भविष्य के लिए साझेदारी, विश्वास पर निर्मित और साझा मूल्यों में निहित" के रूप में वर्णित किया। पीएम मोदी के निमंत्रण पर पीएम ताकाची भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जो पदभार संभालने के बाद उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है और 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है।

विकसित भारत की यात्रा में क्षेत्रीय उद्योगों की अहम भूमिका...

उन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास देश की सुरक्षा को मजबूती देते हैं, जबकि सुरक्षित वातावरण उद्योग और नवाचार के विकास के लिए जरूरी होता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र का विकास केवल हथियारों और सैन्य तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बड़े औद्योगिक इकोसिस्टम को गति देता है। डिफेंस कॉरिडोर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, रोजगार और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के माध्यम से देश की औद्योगिक क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। भारत कभी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर था, अब रक्षा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी प्लेटफॉर्म, निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्टार्टअप्स के योगदान ने देश में मजबूत रक्षा इकोसिस्टम तैयार किया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एयरोस्पेस और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, रक्षा खरीद प्रक्रिया में सुधार, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, आईडेक्स, सृजन पोर्टल और अन्य पहलों के जरिए छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

Your Dreams Destination is here

Pushpam Classes

Classes Also Available on Online Platforms

CBSE ICSE NIOS MUMBAI BOARD

English • Hindi • Marathi Medium
I to XII (Science / Commerce / Arts)

COMPETITIVE EXAMS PREPARATION

Pravinya • Mathex*CV Raman*Science Exam*IPM*
NTSE • NLSTSE • Olympiads KVPY & More

✓ Experienced Faculty
✓ Small Batches & Focused Attention
✓ Regular Tests & Doubt Solving
✓ Excellent Results Every Year

Contact Now:
+91 9220868564
+91 9320868564

Join Us for Academic Excellence!

Step into the Future with ASR Digi!

Imagine exploring properties, products, and places without leaving your home! With our state-of-the-art Virtual Reality Tours, your audience can experience your offerings like never before.

Our Services Include:

- Immersive Virtual Tours
- Captivating Drone Videography
- Realistic 3D Renders
- Scale Models
- Influencer & YouTube Marketing
- Professional Website Development
- Side Branding with LED Screens

Don't just tell your Story-show it in stunning detail!

Contact us today!
Satish Pandey from Navi Mumbai
8879895829 / 9619574572

www.asrdigi.com

उत्तराखण्डे अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियमः प्रवर्तितः, मदरसापरिषद् समाप्ता



देहरादूनमः उत्तराखण्डराज्ये बुधवासरात् आरभ्य उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण यूएसएएमई प्रवृत्तम् अभवत्। अनेन सह उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः तथा अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियमाः समाप्ताः अभवन्। नवीनव्यवस्थायाः अन्तर्गतं राज्यस्य चतुःपञ्चाशदधिकचतुःशत पञ्जीकृतमदरसैः सह सर्वाणि अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानानि निर्धारितनियमावल्यानुसारं मान्यतां प्राप्स्यन्ति। मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी बुधवासरे प्रकाशितसन्देशे अलिखत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनेन राज्यसरकारः आधुनिकां पारदर्शिनीं गुणवत्तायुतां उत्तरदायित्वसम्पन्नां च शिक्षाव्यवस्थां



निर्मातुं प्रतिबद्धा अस्ति। तेन उक्तं यत् नवीनव्यवस्था सवेषां अल्पसंख्यक शैक्षणिकसंस्थानानां कृते समाना पारदर्शिनी च मान्यताप्रणालीं सुनिश्चितं करिष्यति तथा च शिक्षायाः गुणवत्तां उत्तरदायित्वं च सुदृढं करिष्यति। तेन अपि उक्तं यत् सरकारस्य उद्देश्यं प्रदेशस्य बालकान् आधुनिकशिक्षया विज्ञानेन प्रौद्योगिक्या कौशलविकासेन भारतीयजीवनमूल्यैश्च सशक्तान् कर्तुम् अस्ति यथा ते विकसितोत्तराखण्डस्य विकसितभारतस्य च निर्माणे प्रभावपूर्णा भूमिकां निर्वहेयुः। नवीनव्यवस्थायाः अन्तर्गतं राज्यस्य चतुःपञ्चाशदधिकचतुःशत पञ्जीकृतमदरसाः प्रथमं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा बोर्डतः सम्बद्धतां प्राप्स्यन्ति। ततः परम् अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणात् मान्यता प्रदास्यते। प्रत्येकं मान्यतापत्रं त्रीणि

शैक्षणिकवर्षाणि यावत् वैधं भविष्यति। प्राधिकरणाय संस्थानानां निरीक्षणस्य तथा नियमोल्लङ्घने श्रवणप्रक्रियायाः अनन्तरं मान्यतानिरसनस्य अधिकारोऽपि प्रदत्तः अस्ति। राज्यसरकारस्य अनुसारं नवीनव्यवस्था मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन पारसी समुदायानां सवेषां अल्पसंख्यक शैक्षणिकसंस्थानेषु समानरूपेण प्रवर्तिष्यते। संस्थानैः निर्धारिते पोर्टले आवश्यकप्रपत्रैः शुल्केन च सह आनलाइन आवेदनं समर्पणीयम्। अल्पसंख्यककल्याणविभागस्य विशेषसचिवः डा पराग मधुकर धकाते अवदत् यत् एकजुलाईदिनात् आरभ्य प्राधिकरणं नवीनव्यवस्थानुसारं मान्यतासम्बद्धकार्याणि आरब्धवान्। तेन उक्तं यत् एतादृशी व्यवस्थां प्रवर्तयितुं उत्तराखण्डः देशस्य प्रथमं राज्यम् अस्ति। तेन अपि उक्तं यत् नवीनव्यवस्थानुसारं बुधवासरे मध्याह्ने मुख्यमन्त्रिणः आवासे आयोजिते कार्यक्रमे अल्पसंख्यकशिक्षणा ससंस्थानानां मान्यताप्रमाणपत्राणि वितरितानि भविष्यन्ति। तेषु नव अल्पसंख्यक शिक्षणसंस्थानानि मान्यतां प्राप्स्यन्ति। तेषु एकं जैनसंस्थानम् एकं सिखसंस्थानम् सप्त मदरसाः च सन्ति।

रूप्यकस्य अवमूल्यनम् उत अर्थव्यवस्थायाः संकेतः?

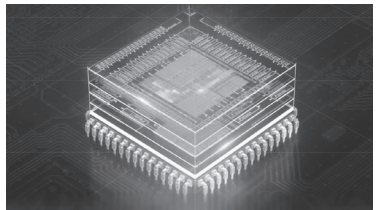
भारतस्य पुरतः संरचनात्मक-सुधारणां नूतनम् आह्वानम्



भारतीयरूप्यकस्य मूल्यह्रासः केवलं पश्चिम-एशियायां वर्धमानेन तनावेन, अन्याभिः वैश्विकाभिः भूराजनैतिक-परिस्थितिभिः अथवा अमेरिकीय-डॉलरस्य सुदृढतया एव न व्याख्यातुं शक्यते। अर्थशास्त्रविशेषज्ञानां कस्यचित् वर्गस्य मते अस्य पृष्ठभूमौ भारतीय-अर्थव्यवस्थायाः केचन गम्भीराः संरचनात्मकाः दोषाः सन्ति, येषां दीर्घकालिकं समाधानम् अत्यावश्यकम् अस्ति। अद्यतनमासेषु भारतीय-रिजर्व-बैंड्रेन तथा भारतसर्वकारेण रूप्यकस्य स्थैर्यरक्षणाय अनेकानि उपायानि स्वीकृतानि। वैदेशिक-पूँजीप्रवाहस्य प्रोत्साहनम्, शासकीय-ऋणपत्रेषु निवेशस्य आकर्षणवृद्धिः तथा प्रवासी-भारतीयेभ्यः विशेष-निक्षेप-योजनानां प्रवर्तनम् इत्यादयः तेषु प्रमुखाः उपायाः सन्ति। एते उपायाः अल्पकालिकं लाभं प्रदातुं समर्थाः सन्ति, किन्तु अर्थव्यवस्थायाः मूलभूतदौर्बल्यानां निराकरणं विना स्थायिसमाधानं न सम्भवति। विशेषज्ञानां मते चीननिर्भरतान्यूननाय विश्वस्तरे प्रवर्तमाना नीतिः भारताय अपेक्षितं फलम् अद्यापि न दत्तवती। विनिर्माणक्षेत्रे प्रत्यक्ष-वैदेशिक-निवेशः अपेक्षया न्यूनः अभवत्, यदा अन्ये केचन एशियादेशाः अस्य अवसरस्य अधिकं लाभम् अलभन्त। अपरतः कृत्रिमबुद्धेः (अक)

तीव्रविकासेन भारतस्य सूचना-प्रौद्योगिकी-क्षेत्रस्य पुरतः नवीनानि प्रतिस्पर्धात्मकानि आव्हानानि समुत्पन्नानि। यदि विनिर्माणक्षेत्रं तथा सूचना-प्रौद्योगिकीक्षेत्रम् – एते भारतस्य आर्थिकविकासस्य प्रमुखौ प्रेरकौ स्तः-अपेक्षितगत्या न प्रवर्धेते, तर्हि निवेशे, निर्याते तथा रोजगारसृजने दीर्घकालिकः प्रतिकूलः प्रभावः सम्भाव्यः। अतः केवलं मुद्राविपण्यां हस्तक्षेपः पर्याप्तः न भविष्यति। भारतस्य स्थायिविकासाय निवेशानुकूलं वातावरणम्, नीतिस्थैर्यम्, उच्च-प्रौद्योगिकी-विनिर्माणस्य विस्तारः, आधुनिक-प्रौद्योगिकीनां विकासः तथा द्वितीय-पीढीय-आर्थिक-सुधारणां प्रवेगः अनिवार्यः। दीर्घकाले निवेशकानां विश्वासः, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धासामर्थ्यं च एव रूप्यकस्य भारतीय-अर्थव्यवस्थायाश्च वास्तविकसुदृढतायाः आधारभूतानि तत्त्वानि भविष्यन्ति।

न्यूनतापे 3D-चिप्-स्तरणप्रौद्योगिकीः अर्धचालक-अनुसन्धाने नूतना प्रगतिः



अमेरिकादेशस्य इलिनॉय-विश्वविद्यालयस्य वैज्ञानिकैः न्यूनतापे 3D-चिप्-स्तरणस्य नूतना प्रौद्योगिकी विकसितेति सूचना प्रदत्ता। प्रारम्भिक-अध्ययनानुसारं एषा विधिः भविष्ये उच्च-प्रदर्शन-सङ्गणनस्य तथा कृत्रिमबुद्ध्याधारित-चिप्-विकासस्य क्षेत्रे उपयुक्ता भवितुम् अर्हति। वैज्ञानिकैः उक्तं यत् एतया पद्धत्या प्रायः २०० डिग्री-सेल्सियस-परिमाणात् न्यूनतापे सिलिकन्-पटलानां बहवः सूक्ष्मस्तराः परस्परम् आरोप्य योजयितुं शक्यन्ते। परम्परागत-3D-चिप्-निर्माणे उच्चतापकारणात् अधस्तन-स्तराणां क्षतिः सम्भवति; नूतना तु प्रौद्योगिकी एतां समस्यां न्यूनीकर्तुं प्रयतते। अनुसन्धानदलस्य मते एषा पद्धतिः भविष्ये एकस्मिन् एव चिप्-पट्टे प्रोसेसर्

स्मृतिसञ्चयः तथा कृत्रिमबुद्धि-त्वरकाः (AI Accelerators) इत्यादीनां घटकानां अधिकदक्षतया एकीकरणे साहाय्यं कर्तुं शक्नोति। यदि परवर्ती-परीक्षणानि सफलानि भवन्ति, तर्हि दत्तांश-विनिमयस्य वेगवृद्धिः, ऊर्जाव्ययस्य न्यूनता तथा इलेक्ट्रॉनिक-उपकरणानां कार्यक्षमतावृद्धिश्च सम्भाव्यते। तथापि एषा प्रौद्योगिकी अद्यापि प्रयोगशाला-स्तरे एव वर्तते। अतः औद्योगिक-प्रयोगात् पूर्वं विस्तृतानि वैज्ञानिक-परीक्षणानि उत्पादन-स्तरीय-सत्यापनं च आवश्यकं भविष्यति। यदि एषा विधिः व्यावहारिकतया सफलतां प्राप्नोति, तर्हि उच्च-प्रदर्शन-सङ्गणनस्य, कृत्रिमबुद्धेः तथा दत्तांश-केन्द्र-प्रौद्योगिक्याः विकासे महत्त्वपूर्ण योगदानं दातुं शक्नोति। अर्धचालक-उद्योगस्य भविष्यं केवलं सूक्ष्मतर-ट्रान्जिस्टर-निर्माणे न निहितम्, अपितु त्रिमितीय-संरचनानां अधिकदक्ष-विकासे अपि निर्भरति। न्यूनतापे 3D-स्तरण-प्रौद्योगिकी तादृशेषु महत्त्वपूर्णेषु अनुसन्धान-प्रयत्नेषु गणनीया अस्ति; अस्याः वास्तविक-उपयोगिता तु भाविष्यानि औद्योगिक-परीक्षणानि एव निश्चितुं शक्नुवन्ति।

आत्मज्ञान-एक्सप्रेसः (राजनैतिक-व्यङ्ग्य नुक्कड़ नाटिका)



Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

मञ्चः मध्यभागे 'सत्ता' इति आसनम्, पार्श्वे जनसमूहः, अग्रे सूत्रधारः (डोसी)। पृष्ठे ढोल-ध्वनिः।
प्रस्तावना (ढोलध्वनिः, डोसी आगच्छति)
डोसी भोः जनाः! अद्य लोकतन्त्रे एका नूतना रेलिका गच्छति
तस्याः नाम 'आत्मज्ञान-एक्सप्रेसः'।
अत्र न टिकटम् आवश्यकम् केवलं 'आसन-दर्शनम्' पर्याप्तम्!

(संकेतः)
डोसी 'आसनं जयतु!'
जनाः 'जयतु!'
दृश्यम् १ : आसन-योगः
(नेताजी परिभ्रमन्ति)
डोसी किमर्थं परिक्रमा?
नेताजी एषः योगः न... एषा 'आसन-साधना'।
(अन्तरात्मा प्रवेशः)
अन्तरात्मा यत्र सत्ता तत्र सत्यं।
नेताजी अहो! एषः एव धर्मः!
डोसी पूर्वं तु अन्यः दलः आसीत्?
नेताजी दलः न परिवर्तते... केवलं 'प्रवेश-स्थानम्' परिवर्तते!
दृश्यम् २ : वचन-व्यवस्था
जनता-१ रोजगारः?
नेताजी प्रक्रिया मध्ये।
जनता-२ महङ्गाई?
नेताजी वैश्विक-विशेषता।
जनता-१ वचनम्?
नेताजी 'डेमो-संस्करणम्'।
अन्तरात्मा लोकतन्त्रे सर्वं trial version!
दृश्यम् ३ : राजनैतिक-समाचारः
डोसी 'बङ्गे 20 सांसदाः नेतृत्वं दुर्बलम्...'
'शिवसेनायाम् उद्धवः निष्क्रियः...'
'AAP-दले 7 सांसदाः केजरीवालं भ्रष्टम्...'
एषः समाचारः न... एषा 'आत्मज्ञान-ऋतुः'!

नेताजीः जागरणम् एतत्!
डोसी नहि! ह्आसन-अपग्रेड सूचनाह् एषा!
दृश्यम् ४ : आसन-संचर्षः
(द्वितीयः नेता आगच्छति)
डोसी आसन-ओलम्पिकम् आरब्धम्!
नेताजी मम विचारधारा!
द्वितीयः नेताः मम 2.0 विचारधारा!
डोसी उभौ सत्यौ... किन्तु सर्वरः भिन्नः!
अन्तरात्मा एषा शक्ति-प्रतियोगिता!
दृश्यम् ५ : जन-दुःखम्
जनता वयं किं कुर्मः?
नेताजी feedbook ignore भविष्यति।
जनता दरिद्राः वयम्!
नेताजी default स्थिति।
अन्तरात्मा अत्र समस्या न समाधीयते... केवलं rebranding भवति!
समापनम्
डोसी अत्र न विचाराः परिवर्तन्ते... केवलं 'सञ्ज्ञाल-व्यवस्था'!
सर्वे 'यत्र आसनं तत्र आत्मज्ञानम्!'
अन्तिम-नाराः
डोसी लोकतन्त्रम् कस्य?
जनाः अस्माकम्!
डोसी आसनं कस्य?
जनाः यः परिवर्तते तस्य!

(पर्दः पतति)

कृत्रिमबुद्धेः नूतना दिशाः किं स्पिन्ट्रॉनिक p-bit प्रौद्योगिकी सङ्गणनस्य भविष्यं निर्धारयिष्यति?

कृत्रिमबुद्धेः (Artificial Intelligence) तीव्रविकासेन सह अधिकदक्षाणां, न्यूनविद्युत्-व्यययुक्तानां च सङ्गणनप्रणालीनाम् आवश्यकता निरन्तरं वर्धते। अस्मिन् परिप्रेक्ष्ये जापान-अमेरिकादेशयोः वैज्ञानिकैः कृतम् अद्यतनम् अनुसन्धानं भविष्यस्य सङ्गणनविज्ञानस्य नूतनां दिशं प्रदर्शयति। जापानदेशस्य तोहोकु-विश्वविद्यालयस्य तथा अमेरिकादेशस्य राष्ट्रीय-मानक-प्रौद्योगिकी-संस्थानस्य (NIST) वैज्ञानिकैः स्पिन्ट्रॉनिक p-bit इत्यस्य विकासे उल्लेखनीया प्रगतिः प्राप्ता। एषा प्रणाली विद्यमानया CMOS-प्रौद्योगिक्या

सह सुसङ्गता अस्ति, अतः भविष्ये अस्याः व्यावहारिकप्रयोगस्य सम्भावना वर्धते। परम्परागतसङ्गणकेषु प्रत्येकः बिट् केवलं ० अथवा १ इत्येतयोः अवस्थयोः एव कार्यं करोति। परन्तु p-bit सम्भाव्यतायाः (Probability) आधारेण उभयोरवस्थयोः मध्ये कार्यं कर्तुं शक्नोति। वैज्ञानिकानां मते इलेक्ट्रॉनकणानां स्पिन्-गुणस्य उपयोगेन एषा प्रणाली नियन्त्रितां यादृच्छिकतां (Controlled Randomness)



सङ्गणनप्रक्रियायाः अङ्गत्वेन स्वीकर्तुं समर्था भवति। एतेन कृत्रिमबुद्धेः, यन्त्राधिगमस्य (Machine Learning) तथा जटिलसमस्यासमाधानस्य क्षेत्रेषु नूतनाः सम्भावनाः उद्घाटिताः भवन्ति। यद्यपि एषा प्रौद्योगिकी अद्यापि अनुसन्धानावस्थायामेव वर्तते, तथापि वैज्ञानिकैः अस्याः भविष्योपयोगिता आशाजनका इति प्रतिपाद्यते। व्यावहारिकप्रयोगात् पूर्वं विस्तृतानि वैज्ञानिकपरीक्षणानि, औद्योगिकसत्यापनं च अनिवार्यं

भविष्यति। प्रयोगशालायां प्राप्ताः परिणामाः प्रत्यक्षतया व्यावसायिकसफलतायाः प्रमाणं न भवन्ति, किन्तु ते अनुसन्धानस्य प्रगतिं अवश्यमेव सूचयन्ति। अद्यतनसङ्गणनाविज्ञानं केवलं अधिकवेगप्राप्तये न प्रयतते, अपितु ऊर्जा-दक्षता, बुद्धिमत्ता तथा जटिलगणनासु अधिकसामर्थ्यस्य विकासमपि लक्ष्यीकुरुते। स्पिन्ट्रॉनिक p-bit प्रौद्योगिकी तस्यैव परिवर्तनस्य प्रारम्भिकसूचना इव दृश्यते। यदि भाविष्यानुसन्धानानि अपेक्षितसफलतां प्राप्स्यन्ति, तर्हि कृत्रिमबुद्धेः उच्च-प्रदर्शन-सङ्गणनस्य च क्षेत्रे एषा प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्णं स्थानं प्राप्तुं शक्नोति।

Major cabinet reshuffle may happen soon in Modi government

Discussion of changing departments of many ministers

New Delhi: Speculations about cabinet expansion and reshuffle in the Narendra Modi government at the Center have intensified. According to the signals coming from the top level of the ruling establishment, changes in the Union Council of Ministers can be made at any time. It is believed that this reshuffle may happen before the upcoming monsoon session of Parliament or during July. According to sources, along with the changes in the Union Cabinet, the new team of BJP President Nitin Naveen can also be announced. It is being told that the BJP leadership has almost finalized the list of the new team, in which young faces can get important responsibilities in the organization. According to sources, the BJP President also held a meeting with some Union Ministers of State last week.



There is a possibility that some Union ministers may be given responsibility in the organization, while some officials of the BJP organization may be made ministers in the Modi government. Apart from this, there is also talk of changes in the departments of many ministers. The name of Union Education Minister Dharmendra Pradhan is also in discussions. Questions have been raised about his ministry after the controversies related to NEET paper leak and CBSE's digital assessment system.

Decision may be taken soon

■ Sources say that the date of cabinet expansion will be decided in view of Prime Minister Narendra Modi's busy foreign tour. The Prime Minister is on a visit to Seychelles from 27 to 29 June. After this, a trip to Indonesia, Australia and New Zealand is also proposed between 6th to 11th July. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi will be on a visit to India from 1 to 3 July. In such a situation, there is a possibility that there may be a cabinet reshuffle sometime in July amid these programs.

Special focus will be on electoral states

■ According to sources, assembly elections are to be held in Uttar Pradesh, Uttarakhand and Punjab next year. In such a situation, more representation from these states can be seen in the cabinet. After the better performance of BJP in West Bengal, some MPs from there are

also expected to get a place in the cabinet. Also, some leaders who left Trinamool Congress and Shiv Sena (Uddhav faction) and joined NDA can also be made ministers, although this decision will be possible only after the decision of the Lok Sabha Speaker on matters related to anti-defection law.

Signs of implementation of 'one man, one post' rule

■ Union Ministers Pankaj Chaudhary and Harsh Malhotra have got the responsibility of Uttar Pradesh and Delhi BJP respectively. In such a situation, there is a possibility of him leaving the ministerial post under the 'one man, one post' principle of BJP.

At the same time, Union Minister George Kurien has resigned after the end of the tenure of Rajya Sabha. On the other hand, Ravneet Singh Bittu still remains a minister, but there is talk of giving him the responsibility of focusing on the Punjab Assembly elections.

Appointments can also be made on Governor posts

■ According to sources, some of the ministers who will be dropped from the cabinet may be made governors. The tenures of Karnataka Governor Thawarchand Gehlot, Madhya Pradesh Governor Mangubhai

Patel and Uttarakhand Governor Lieutenant General Gurmeet Singh are set to be completed in the coming months. However, political experts say that Prime Minister Narendra Modi keeps big decisions confidential till the last moment.

When Medicine Meets Music

A Lesson in Lifelong Learning

The premiere of Brain Makes Music was more than the launch of a documentary. It celebrated the enduring power of curiosity, creativity and lifelong learning, reminding the audience that meaningful contribution knows no age.

Padma Bhushan Dr. Farokh E. Udwadia (93) and renowned psychiatrist Dr. Ashit Sheth (81) at the premiere of Brain Makes Music in Mumbai. The event celebrated medicine, music, creativity and the enduring power of lifelong learning.



Mumbai: The Nehru Centre Auditorium witnessed an inspiring gathering as Padma Bhushan awardee Dr. Farokh E. Udwadia (93) and renowned psychiatrist Dr. Ashit Sheth (81) came together for the premiere of Brain Makes Music. The event highlighted the unique intersection of medicine, music and lifelong learning through the experiences of two physicians whose careers continue to inspire generations. Speaking on the occasion, Dr. Sheth reflected on his decision to pursue psychiatry at a time when the discipline received limited recognition.

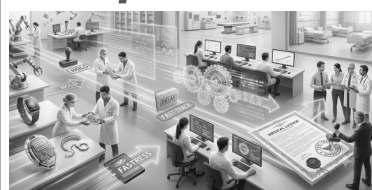
He emphasized the importance of compassion, scientific inquiry and evidence-based mental healthcare, while explaining that his lifelong interest in the relationship between music and the human brain inspired the documentary. In the keynote address, Dr. Udwadia explored music through the perspectives of history, philosophy, neuroscience and medicine. He described music as more than an art form, noting its influence on emotion, memory, cognition and rehabilitation. His lifelong engagement with the violin, alongside an eminent medical career, illustrated the harmony between scientific excellence and creative expression.

More than a cultural programme, the evening became a reflection on the value of intellectual curiosity and continuous learning. The lives of both physicians demonstrated that age does not define one's capacity to innovate, mentor or contribute to society. Their journey conveyed a timeless message: the most fulfilling years of life are those in which we continue to learn, create and serve.

Editorial Note: This report is based on the proceedings of the event and publicly available information. It is intended to highlight the significance of lifelong learning, interdisciplinary thinking and service to society.

Medical device licensing process will be faster

Proposal to amend the rules



New Delhi: The Central Government has issued draft amendments to the Medical Devices Rules, 2017 to provide relief to the medical device industry. The proposed changes are aimed at making the process of issuing production licenses for medical devices more simple, transparent and time-bound, so that the industry can get faster approvals without compromising on quality, safety and performance standards. According to the draft notification issued by the Health Ministry, the time limit for issuing licenses will be reduced as per the risk-based cat-

egories. Under current regulations, medical devices are classified into classes A, B, C and D, with Class D being the highest risk category. According to the proposal, the time frame for manufacturing licenses for Class B (medium risk) devices—such as blood pressure monitors, hypodermic needles and pulse oximeters—is proposed to be reduced from 140 days to 115 days. For high-risk Class C and D devices, such as cardiac stents, hip and knee implants and other orthopedic implants, the time for issuing licenses is proposed to be reduced from 105 days to 90 days. It has been proposed to do so. The draft amendment also provides for clearly specifying timelines for each stage of the licensing process—scrutiny of applications, audit by listed entities, verification of compliance and issuance of final license.

Today the world is looking towards India with hope : Anurag Thakur



Shimla: BJP MP Anurag Thakur performed darshan and worship at Jakhu Hanuman Temple in Shimla. During this, he talked about the leadership of PM Modi and stressed on responsibility towards cleanliness and environment in the state. During this, he said that today the world is looking towards India with hope. Anurag Thakur told IANS, "It is not that when you come to the feet of God, you come only to ask for something. Jakhu Hanuman Temple is a very old

place. If you see the beautiful views around it, then a feeling of positive energy automatically awakens within you. I believe that whoever comes to Shimla and does not visit Jakhu temple, his journey remains incomplete in a way." MP Anurag Thakur said, 'The world is looking towards India. India is the fifth largest economy in the world. It has the highest population. India is self-reliant in every field and Prime Minister Narendra Modi has pledged to make India developed by 2047. The Prime Minister led us for 12 years. The Prime Minister's efficient leadership helped the country overcome the Covid, West Asia crisis. I pray to Hanumanji to give more strength to the Prime Minister.'

CM Yogi speaks on delay in disposal of revenue cases

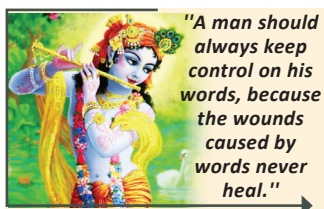
Provide justice within time limit

Lucknow: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath listened carefully to the problems of the complainants from different districts of the state in 'Janata Darshan'. Took their application form and gave it to the concerned authorities and directed that the problems of all the people should be resolved within the stipulated time. After this, the victim should be talked to and information about their satisfaction should be obtained. The Chief Minister assured the victims and said that they should go home without any worry, we will get every case resolved properly. A woman who came from Bareilly met the Chief Minister. He appealed to the CM for cancer treatment and sought financial assistance. CM asked



her for the estimate of the hospital, which she could not provide immediately. On this the Chief Minister said that you should get the estimate from the hospital. You pay attention to your health, the government will take care of the treatment. The Chief Minister also directed to get the patient admitted and for his proper treatment. Revenue related matters

also came up in 'Janata Darshan'. On this the Chief Minister said that the government will not tolerate encroachment at all. Continuous action will continue on this. The CM also stressed on timely disposal of revenue cases and said that quick decision on these provides timely relief to the litigants. Revenue officials should sit in the court on time. The decision in this regard should also be given soon, because if this is not done then the poor litigants are more affected. It is the government's intention to provide justice to the litigants.



PUPILS TIMES

For the one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never invisible to him, nor is he invisible to me.
Geeta Sermon



Friday, 3 July to 9 July 2026

Healing with Light : Could Smart OLED Patches Redefine Diabetic Wound Care?



Dr. Arvind Singh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon Coloproctologist
FACRSI, FAMS FIAGES

The convergence of bioelectronics, materials science and precision medicine is opening new possibilities

for the treatment of chronic diseases. A wearable OLED-based therapeutic patch developed by researchers in South Korea offers a glimpse into this evolving landscape. Although the technology remains at the preclinical stage, it highlights how future wound care may become more intelligent, responsive and patient-centred. Diabetic wounds continue to represent one of the most complex challenges in modern medicine. Delayed healing, recurrent infections and prolonged treatment not only affect a patient's quality of life but also place a substantial burden on healthcare systems worldwide. These challenges have encouraged researchers to explore therapeutic technologies



that can respond more precisely to the biological condition of a wound. Researchers from the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), the Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology (KICET) and Chungbuk National University have developed a wearable OLED-based therapeutic patch that integrates photobiomodulation with controlled drug delivery. According to the research team, the device is designed to regulate the release of antioxidant medication in response to biological signals generated during light therapy, allowing treatment to adapt to the wound's physiological requirements.

The reported findings are based on preclinical studies in animal models and should therefore be interpreted with appropriate scientific caution. Comprehensive clinical trials in humans remain essential before the technology can be considered for routine medical practice. Nevertheless, the research demonstrates how wearable bioelectronics may contribute to the next generation of personalised wound management. For countries

facing a rising prevalence of diabetes, including India, innovations of this kind deserve close scientific attention. Their eventual impact, however, will depend on rigorous clinical validation, regulatory evaluation, accessibility and integration into healthcare systems.

As with every meaningful medical advance, evidence not expectation will determine whether this promising technology ultimately finds a place in everyday clinical care.

This article is based on publicly available scientific literature and institutional research announcements. It is intended solely for educational and analytical purposes and should not be interpreted as medical advice or as an endorsement of any technology.

«Maharashtra Government's order»

Marathi compulsory from class 1st to 10th



Action will be taken against those who do not follow the rules

■ Responding to these allegations, School Education Minister Dada Bhuse said that the state government is fully committed to the preservation and promotion of Marathi language. He said that soon a special inspection campaign will be started across the state, under which all the schools will be inspected. If rules are not followed in any school, strict action will be taken against the concerned officials and management. In the Assembly, the Minister also shared important information regarding the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He said that earlier in the textbooks of many other education boards of the country, the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj was limited to only about one and a half columns. Now after the approval of the Central Government, it has been expanded to 22 pages, so that students will be able to get detailed information about his life and contribution.

Emphasis on the glorious history of Chhatrapati Shivaji

■ Dada Bhuse said that the objective of the state government is not only to promote Marathi language but also to connect the new generation with the glorious history and cultural heritage of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He assured that adherence to the prescribed rules will be ensured in all schools and negligence or ignoring the rules will not be tolerated at any level.

Mumbai: Maharashtra government has decided to make teaching of Marathi language mandatory from class 1st to 10th in all mediums and schools affiliated to all education boards in the state. The government has made it clear that a special investigation campaign will be conducted in the entire state to ensure strict compliance with this order. If it is found that Marathi language is not being taught compulsorily in any school, then strict action will be taken against the concerned officials. State School Education Minister Dada Bhuse gave this information in the Assembly on Monday. This issue was raised by BJP MLA Atul Bhatkalkar through a question in the Assembly. During the discussion, many other MLAs also asked supplementary questions and alleged that Marathi language is not being taught in many schools of the state despite the rules.

JP Nadda launches digital health services

Ayushman Sarathi chatbot launched



New Delhi: Union Health Minister JP Nadda on Monday launched several digital initiatives, including 'Ayushman Sarathi-PM-Jai WhatsApp Chatbot' and drug registry. These are aimed at better and effective delivery of health services and increasing the satisfaction of the beneficiaries. This chatbot provides essential PM-JAY services to the beneficiaries anywhere and anytime, thus eliminating the need for them to visit government offices or call centres. The minister told an event that this system is connected to the PM-JAY system through secure API based integration and provides real-time information and services on WhatsApp itself. Through Ayushman Sarathi, beneficiaries will get many services like eligibility check under PM-JAY, viewing Ayushman card, applying for card, card download, e-KYC update, linking Aadhaar, locking/unlocking PM-JAY card and Ayushman Vaya Vandana card for people above 70 years of age. According to the Health Ministry, this chatbot has been designed in such a way that it makes services more accessible, transparent and citizen-centric. With this, people will get immediate services, dependence on call centers and offices will be reduced and the process of filing complaints will also be easier.

Threat to blow up ISRO headquarters

Bengaluru: The headquarters of the Indian Space Research Organization (ISRO) in Bengaluru has received a bomb threat. According to the police, a threatening e-mail has been received by the man Dr. V. Na-



e-mail sent to chairman

bomb squad are investigating at the headquarters. The investigation has been started immediately after receiving the threatening mail. According to the police, a threatening e-mail was sent to the office of ISRO Chairman Dr. V. Narayanan. Only after receiving the alert, the police teams reached ISRO headquarters. The bomb squad team also reached the spot. The bomb squad team thoroughly searched the ISRO headquarters premises. No explosive item was found during the search. Several police teams are investigating to trace the sender of the e-mail and find out the motive. Officials are also investigating whether this e-mail was sent from outside the country.

Dr Jitendra Singh lays foundation stone of 44.46 crore hostel at CSIR-IICT, inaugurates four R&D facilities

New Delhi: Union Minister of State for Science and Technology (Independent Charge) Dr Jitendra Singh laid the foundation stone of a new hostel to be built at a cost of Rs 44.46 crore at CSIR-Indian Institute of Chemical Technology (CSIR-IICT), Hyderabad. On the occasion, he also inaugurated four state-of-the-art Research and



Development (R&D) facilities and said that strong partnerships between agricultural research and industry will drive the next

phase of India's economic growth. Dr Jitendra Singh said that agricultural research, waste-to-wealth technology and practical application of research are creating new opportunities for farmers, micro, small and medium enterprises (MSMEs) and startups.

He said that industrial development and environmental protection can move forward together and this will become an important basis towards a developed India.

PUPILS TIMES
Core Committee
Shivprakash Pandey Chief Publisher
Vikas Maurya Co Publisher
Address : Shop No.3, Khatri NX Apt.,
Valivali, Badlapur (West) - 421503.
Web : pupilstimes.com

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
"With you in life, and after life"
POPULAR LIC PLANS:
✓ **Jeevan Labh** — Limited Premium, High Returns
✓ **New Children's Money Back** — Secure Your Child's Future
✓ **Jeevan Umang** — Whole Life Cover + Pension Benefits
✓ **Bima Jyoti** — Guaranteed Additions, Safe Growth
✓ **Also Available** — Complete Financial Planning Guidance
KEY BENEFITS:
✓ Life Insurance + Savings Plan
✓ Child Education and Marriage Planning
✓ Retirement Planning
✓ Tax Benefits Available

भारतीय जीवन वीमा निगम
"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी"
FREE POLICY CONSULTATION
LIC Agent
Archana Shukla
☎ +91 91129 39085
☎ +91 74998 67628
Shop No. 2, Near Vithal Mandir,
New Vadavali Chowk,
Badlapur (West) - 421503
LIC Agent ID: 04497939

ANURAG SHUKLA CHIEF EDITOR . Mob.: +91 9167378057, E-mail: anurag@pupilstimes.com. www.pupilstimes.com

Printed, Published & Owned by : **ANIL MISRA**, Printed at **SOMANI PRINTING PRESS**, UNIT NO. 04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E.), MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at** : 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA). (The editor does not necessarily agree with the news, article and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai court) Editor - **ANIL MISRA**, Mob. : 92208 68564, Email : anilmisrapc@gmail.com. **PRGI. No. : MHMUL/25/A2419**